

नीतीश मिश्रा (स.वि.स.)

पूर्व मंत्री
बिहार सरकार



पत्रांक 38/15

दिनांक 19/05/201

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

महाशय,

हमारे पूर्व के पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.2014 के साथ संलग्न अनुलग्नकों की छाया प्रति का अवलोकन किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा ये सूचित किया गया था कि श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम— अररिया संग्राम (झंझारपुर) जिला— मधुबनी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी का एन०एच०— 57 के निर्माण के क्रम में इन आवेदकों की जमीन भी अर्जित की गई थी। परंतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक इन्हे नहीं दिया गया है। जबकी न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन मध्यस्थ पदाधिकारी ने बाजार मूल्य 68,810/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुछ लोगों को उनके जमीन के मुआवजा की राशि दी गई है।

अतएव ऐसी परिस्थिती में भू धारियों के बीच आक्रोश व्याप्त है, जिससे अप्रिय घटना घटने की संभावना भी बनती जा रही है। इसलिए आग्रह है कि इन तथ्यों की जाँच अपने स्तर से करते हुए उन्हें शीघ्र मुआवजा भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitesh Mishra
(नीतीश मिश्रा) 12.5.13

अनुलग्नक:-

1. पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.14 की छायाप्रति।
2. आवेदकों के आवेदन की छायाप्रति एवं न्यायालय आदेश सं० 17/2010-11 दिनांक 31.07.10 के आदेश की छायाप्रति।

नीतीश मिश्रा (स.वि.स.)

पूर्व मंत्री

बिहार सरकार



पत्रांक 37/15

दिनांक 12/05/201

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

महाशय,

हमारे पूर्व के पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.2014 के साथ संलग्न अनुलग्नकों की छाया प्रति का अवलोकन किया जाए। उक्त पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा ये सूचित किया गया था कि श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम- अररिया संग्राम (झंझारपुर) जिला- मधुबनी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के निवासी का एन०एच०- 57 के निर्माण के क्रम में इन आवेदकों की जमीन भी अर्जित की गई थी। परंतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक इन्हे नहीं दिया गया है। जबकी न्यायालय के आदेश के आलोक में तत्कालीन मध्यस्थ पदाधिकारी ने बाजार मूल्य 68,810/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुछ लोगो को उनके जमीन के मुआवजा की राशि दी गई है।

अतएव ऐसी परिस्थिती में भू धारियों के बीच आक्रोश व्याप्त है, जिससे अप्रिय घटना घटने की संभावना भी बनती जा रही है। इसलिए आग्रह है कि इन तथ्यों की जाँच अपने स्तर से करते हुए उन्हे शीघ्र मुआवजा भुगतान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

शुभकामनाओं के साथ,

अनुलग्नक:-

1. पत्रांक 665/नि० दिनांक 02.09.14 की छायाप्रति।
2. आवेदकों के आवेदन की छायाप्रति एवं न्यायालय आदेश सं० 17/2010-11 दिनांक 31.07.10 के आदेश की छायाप्रति।

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, मधुबनी को सभी अनुलग्नकों की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(नीतीश मिश्रा)

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 12.5.15

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्री
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार
- सह -

अध्यक्ष
राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
बिहार

पत्रांक/Ref No 665/नि

दिनांक/Dated : 2/9/14

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री बालाकांत झा एवं अन्य ग्राम-अररिया संग्राम (झंझारपुर), मधुबनी द्वारा समर्पित आवेदन तथा साक्ष्य से संबंधित कागजात संलग्न है । आवेदकगण मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं । आवेदन में वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि एन0एच0-57 के निर्माण के क्रम में अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे का भुगतान नहीं हाने से ये सभी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं ।

संलग्न आवेदन एवं अनुलग्न कागजातों में वर्णित तथ्यों के आलोक में मुआवजा भुगतान हेतु समुचित कार्रवाई करना चाहेगें ।

शुभकामनाओं के साथ,

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 2.9.14

सेवा में,

माननीय मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- सरकार द्वारा कृषकों से राष्ट्रीय उच्च पथ-57 के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा दिलाने के संबंध में ।

महाशय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण के क्रम में एन0एच0-57 के मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अनुमण्डल एवं झंझारपुर अंचल के अररिया संग्राम पथांश के लिए कई कृषकों एवं रैयतों की जीविका के मुख्य आधार वाली भूमि का अर्जन कर सरकार ने एन0एच0ए0आई0 को दिया है जिसमें कई रैयतों को मुआवजे का भुगतान किया गया परन्तु हम रैयतों को अब तक मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है । इस संदर्भ में श्रीमान का ध्यान निम्न विन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहेंगे -

1. भू-अर्जन की कार्रवाई के अधीन वर्ष 2005-06 में गजट प्रकाशित कर अर्जित भूमि के संबंध में विवरण एवं आपत्ति आमंत्रित की गयी ।

2. हम लोगों ने विधिवत आपत्ति दायर कर अर्जित होने वाली भूमि के बाजार मूल्य में संशोधन कर उचित मुआवजे का अनुरोध किया । तदालोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा कई रैयतों को मुआवजे का भुगतान भी हुआ ।

3. वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में रैयतों को मुआवजे की राशि वितरित करने की कार्रवाई चलती रही परन्तु कतिपय कारणों से वर्ष 2009-10 में भुगतान अवरूद्ध रहा । पुनः वर्ष 2010-11 से भुगतान की कार्रवाई की गयी फलस्वरूप अररिया संग्राम मौजा के लगभग 80 प्रतिशत भूधारियों को भुगतान कर दिया गया है ।

4. हम सभी भूधारियों की भूमि व्यवसायिक प्रकृति की है तथा इस भूमि पर स्वयं रोजगार कर अथवा व्यवसायिक कार्य हेतु किराये पर भूमि अथवा निर्मित मकान देकर अपना जीविका चला रहे थे ।

5. उचित मुआवजे की भुगतान नहीं होने की स्थिति में कई भूधारियों द्वारा मध्यस्थ पदाधिकारी के समक्ष अपील भी दायर की गयी । जिसमें मध्यस्थ पदाधिकारी ने भुगतान में हो रहे विलंब एवं भूमि के प्रकृति के अनुरूप निर्धारित तत्कालीन बाजार मूल्य 68,810/- रुपये प्रति डिसिमल तथा पूर्व से दिये जा रहे मुआवजे की दर से ब्याज सहित वर्ष 2007 में निर्गत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति के अनुरूप भुगतान का आदेश पारित किया । इस आदेश के आलोक में भी कतिपय लोगों को भुगतान भी किया गया परन्तु हम 10 भूधारियों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है । भू-अर्जन अपील वाद सं0-17/2010-11 में दिनांक 31.07.2010 पारित आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है

जिससे स्पष्ट होगा कि भू-अर्जन के समय 68,810/- रुपये प्रति डिसिमिल थी तथा अन्य प्रकार के सोलेशियम एवं बोनस के साथ-साथ ब्याज देय है ।

6. हम भूधारी भी मध्यस्थ पदाधिकारी के समक्ष अपील वाद दायर कर चुके हैं तथा मध्यस्थ पदाधिकारी द्वारा पक्ष में आदेश भी निर्गत किया गया है । सुलभ प्रसंग हेतु आदेश की प्रति संलग्न है ।

7. मध्यस्थ पदाधिकारी के आदेश एवं विहित प्रावधान के बावजूद भी भुगतान नहीं होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर कर मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया गया । सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0-10854/2013 में दिनांक-23.06.2014 को पारित न्यायादेश में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को न्यायादेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर मुआवजे की भुगतान करने का निदेश दिया गया है । संदर्भित न्यायादेश की प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है ।

8. हम सभी भूधारियों की सूची भूमि के विवरण के साथ अलग से संलग्न किया जा रहा है जिसमें एल0ए0 संख्या के साथ-साथ सन्निहित प्लॉट एवं रकबा अंकित किया गया है ।

9. सभी प्रकार के न्यायादेशों तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 (संकल्प, दिनांक 19.02.2007) के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि हम भूधारियों को जानबुझकर मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा रहा है । यद्यपि कतिपय लाभुकों को 68,810/- प्रति डिसिमिल तथा अन्य देय अतिरिक्त राशि की दर से ब्याज सहित भुगतान किया गया है और उसी मौजा, प्लॉट, संलग्न प्लॉट, किस्म आदि की हमारी भूमि के लिए अब तक भुगतान लंबित है ।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि हम सभी भूधारियों को अर्जित भूमि के विरुद्ध मध्यस्थ पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के परिप्रेक्ष्य में ब्याज सहित मुआवजे का भुगतान कराने की कृपा की जाय, जैसा कि अन्य भूधारियों को भी पूर्व में किया जा चुका है । इस उपकार के लिए हम सभी भूधारी कृतज्ञ रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

तिथि :- 02.09.2014

स्थान :- पटना

बालाकान्त का पिता एवं कल्याण का
शाम + पौठ - अड़िया संगम अंचल
अंकारपुर जिला मधुबनी

Mob - 9931368685
9431826371

- 1) Bala Kant Jha
- 2) अचल लाल मंडल
- 3) प.पु.पा.र.ग.०१११
- 4) राम मिलन शाह
- 5) राम प्रवेश मंडल
- 6) सुश्रवण 61क/
- 7) फि र न मि श्र
- 8) सुरभी 6क/
- 9) राम (ग.प.का)

Sl. No.	Particulars	LN/NO.	AMOUNT	CR/DR/10	Balance
	श्री लाली न. 1111				
	श्री लाली कार्यालय का खिना	204	1700/-	2328	Balance Kant 200
	सं. 205		346	2329	
	सं. 206			2330	
	सं. 207				
02	श्री लाली कार्यालय का खिना	201	1700/-	2327	श्री लाली कार्यालय का खिना
	सं. 202		346	2328	
	सं. 203			2329	
03	श्री लाली कार्यालय का खिना	185		2262	श्री लाली कार्यालय का खिना
	सं. 186			2312	
	सं. 187			2314	
	सं. 188			2316	
05	श्री लाली कार्यालय का खिना	190		2251	श्री लाली कार्यालय का खिना
	सं. 191		532	2142	
06	श्री लाली कार्यालय का खिना				
07	श्री लाली कार्यालय का खिना	23		2096	श्री लाली कार्यालय का खिना
08	श्री लाली कार्यालय का खिना	42		2166	श्री लाली कार्यालय का खिना
	सं. 2167			2167	
	सं. 2168			2168	
	सं. 2169			2169	
	सं. 2170			2170	
09	श्री लाली कार्यालय का खिना	176		2258	श्री लाली कार्यालय का खिना

श्री लाली कार्यालय का खिना

श्री लाली कार्यालय का खिना